compensate the SEB's by providing adequate budgetary support. When tariffs are rationalized and budgetary support is provided, the SEB's will improve their financial health and their capacity to invest. This would also ensure that there is no need for Government guarantees, counter-guarantees and operating of escrow accounts. This in turn will help in flow of greater resources, both public and private, into the power sector, thereby improving the power position considerably. This will go a long way in enabling the SEBs in investing on critical works such as renovation and modernisation of existing generation facilities, improvements of transmission and distribution systems etc. In the long run, this will have the effect of optimising operational performance, reducing the T & D losses and improving the quality of power supplies to the consumers and thereby making the consumers and thereby making the power sector self-sustained. The Regulatory Commissions are expected to structure tariffs realistically once they become functional.

(c) The establishment of the Electricity Regulatory Commissions is mandated by the Common Minimum National Action Plan for Power (CMNPP) which was finalised after two Conferences of Chief Ministers held in 1996. As per the Ordinance, the Regulatory Commissions are to be set up within a period of three months from the date of the commencement of the Ordinance (25-4-1998).

राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत निगम का गठन

827. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत निगम" गठित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत सरकार विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं इस संबंध में लक्ष्य अर्जित करने हेतु विद्युत की वर्तमान व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करने और "राज्य ग्रामीण विद्युत निगम" गठित करने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायत राज संस्थाओं को ग्रामीण विद्युतीकरण का दायित्व सौंपने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) जी, नहीं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम पहले से ही विद्यमान है।

(ग) और (घ) संविधान में 73वें संशोधन के पश्चात् ग्रामीण विद्युतीकरण और वितरण का कार्य राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्था को सौंपा जा सकता है।

Effect on power supply due to nuclear test

828. SHRI GOVIND RAM MIRI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that power sector in the country has been/is likely to be adversely affected by sanctions imposed/threatened by different countries following our recent Nuclear tests;

(b) if so, steps taken by Government to combat the same?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) According to information available at present, the committed external assistance for the power sector is not likely to be affected by the sanctions imposed or threatened by the donor countries. In case of any adverse impact, Government will ensure alternative sources of finance, so that the momentum of investment in the power sector is not affected.

विद्युत वित्त निगम की भूमिका

829. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम को आपूर्ति संबंधी असंतुलन कम करने में कोई विशेष सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार राज्य-वार कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ग) विद्युत वित्त निगम उन विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है जिनके कार्यान्वयन विद्युत आपूर्ति में होने वाले घाटे को कम करने में सहायता मिलती है। गत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा प्रदान किए गए ऋण का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।